



नई दिल्ली, सोमवार 27 जुलाई 2026

सच्ची ख़बर, सबकी ख़बर...



www.madhyaswarnim.com

पेपर लीक व गड़बड़ी रोकने के लिए सरकार उठाएगी कड़े कदम

परीक्षा सुधारों पर पीएम मोदी का बड़ा एलान : नंदन नीलेकणि के नेतृत्व में बनेगा उच्चस्तरीय कार्यबल

मध्य स्वर्णिम, नई दिल्ली।

परीक्षा प्रणाली में सुधार और छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार शाम बड़ा एलान किया। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया माध्यमों पर जारी वीडियो संदेश में बताया कि देश की परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए विश्व प्रसिद्ध प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणि के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय कार्यबल का गठन किया गया है। यह कार्यबल परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, भरोसेमंद और तकनीक आधारित बनाने के लिए आवश्यक सुधारों पर काम करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए लगातार कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और ऐसे कड़े आरोपी आज जेल में हैं। उन्होंने यह भी कहा कि परीक्षा से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की व्यवस्था की गई है और सरकार संसद में ऐसे नए कानून की दिशा में भी आगे बढ़ रही है, जिसमें दोषियों के खिलाफ कड़े कानूनी प्रावधान किए जाएंगे।



परीक्षा व्यवस्था में तकनीक का बढ़ेगा इस्तेमाल

■ प्रधानमंत्री ने कहा कि बदलते समय और भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए देश की परीक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव की आवश्यकता है। परीक्षाओं को केवल आयोजित करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि पूरी व्यवस्था में विद्यार्थियों और अभिभावकों का भरोसा कायम होना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए, जिसमें पारदर्शिता के साथ-साथ तकनीक का अधिकतम उपयोग हो और किसी भी स्तर पर अनियमितता की गुंजाइश कम से कम हो। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए नंदन नीलेकणि के नेतृत्व में गठित उच्चस्तरीय कार्यबल परीक्षा व्यवस्था की मौजूदा प्रणाली का अध्ययन करेगा और उसमें आवश्यक सुधारों को लेकर अपनी सिफारिशें देगा। प्रधानमंत्री ने संकेत दिया कि कार्यबल की रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार जल्द से जल्द जरूरी कदम उठाएगी। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी छात्र को परीक्षा व्यवस्था की खामियों का खामियाजा न भुगतना पड़े।

दोषियों पर कार्रवाई, छात्रों के हित में सरकार के कदम

अब बदलेगी देश की परीक्षा व्यवस्था, नंदन नीलेकणि के नेतृत्व में हार्ड पावर टास्क फोर्स



फास्ट ट्रैक अदालतों से जल्द निपटेंगे मामले

■ उन्होंने बताया कि पिछले ढाई महीनों में परीक्षा से जुड़ी अनियमितताओं और पेपर लीक के मामलों में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें जेल भेजा गया है। साथ ही, छात्रों का एक साल खराब न हो, इसके लिए कम समय में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित कर परिणाम भी जारी किए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि परीक्षा से जुड़े अपराधों और पेपर लीक के मामलों का जल्द निपटारा भी जरूरी है। इसके लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना की दिशा में कदम उठाए गए हैं। सरकार का प्रयास है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई लंबे समय तक लंबित न रहे और विद्यार्थियों तथा उनके अभिभावकों को समय पर न्याय मिल सके। इसके अलावा सरकार संसद में परीक्षा व्यवस्था से जुड़े अपराधों के खिलाफ कड़े कानूनी प्रावधानों वाला नया कानून लाने की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। इससे परीक्षा में संध लगाने, पेपर लीक करने और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले लोगों पर प्रभावी कार्रवाई का रास्ता मजबूत होने की उम्मीद है।

कौन हैं नंदन नीलेकणि ?

■ नंदन नीलेकणि देश के प्रमुख प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों में शामिल हैं। उनका जन्म 2 जून 1955 को बंगलूरु में हुआ था। उन्होंने आईआईटी बंबई से विद्युत अभियांत्रिकी की पढ़ाई की। वर्ष 1981 में उन्होंने एनआर नारायण मूर्ति और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर इंफोसिस की स्थापना की। वे कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और बाद में गैर-कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। नंदन नीलेकणि को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में भी जाना जाता है। उनके नेतृत्व में आधार जैसी देश की महत्वपूर्ण डिजिटल पहचान परियोजना को आगे बढ़ाया गया। उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। डिजिटल क्षेत्र में उनके व्यापक अनुभव को देखते हुए अब परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्चस्तरीय कार्यबल की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है।



धर्मेंद्र प्रधान के एगिजट के बाद प्रल्हाद जोशी की एंट्री, नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने संभाला पदभार

मध्य स्वर्णिम, नई दिल्ली।

नीट पेपर लीक विवाद के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में बड़ा बदलाव हुआ है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के एक दिन बाद रविवार को केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। प्रल्हाद जोशी अपने मौजूदा मंत्रालयों की जिम्मेदारियां भी संभालते रहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने वाले प्रल्हाद जोशी के सामने सबसे बड़ी चुनौती देश की परीक्षा व्यवस्था में छात्रों का भरोसा बहाल करना होगा। नीट पेपर लीक विवाद के कारण देशभर में छात्रों और अभिभावकों के बीच नाराजगी का माहौल है। ऐसे में नई जिम्मेदारी संभालते ही परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाना उनके लिए प्राथमिकता माना जा रहा है। धारवाड़ से पांच बार लोकसभा सांसद रहे प्रल्हाद जोशी केंद्र सरकार में कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं।

परीक्षा सुधार सबसे बड़ी प्राथमिकता

■ उन्हें प्रशासनिक और संगठनात्मक मामलों का लंबा अनुभव है। वर्ष 2019 से 2024 के बीच उन्होंने संसदीय कार्य मंत्रालय के साथ-साथ कोयला और खान मंत्रालय की जिम्मेदारी भी संभाली। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र सरकार में उन्हें उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार दिया गया था। अब शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलने के बाद उनके सामने एक नए और संवेदनशील क्षेत्र को संभालने की चुनौती होगी। प्रल्हाद जोशी के सामने सबसे महत्वपूर्ण चुनौती देश की परीक्षा प्रणाली में सुधार की होगी। नीट समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोपों ने परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में नए शिक्षा मंत्री को परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा, प्रश्नपत्रों की गोपनीयता, डिजिटल तकनीक के सुरक्षित इस्तेमाल और परीक्षा संचालन की पूरी प्रक्रिया को मजबूत करने की दिशा में काम करना होगा। साथ ही छात्रों को यह भरोसा दिलाना भी जरूरी होगा कि मेहनत और योग्यता के आधार पर होने वाली परीक्षाओं में किसी भी तरह

चढ़ावा चोरी विवाद : सुप्रीम कोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई

नई दिल्ली। अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान और चढ़ावे के प्रबंधन में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। शीर्ष अदालत उत्तर प्रदेश सरकार से जांच कर रही विशेष जांच दल (एसआईटी) के पुनर्गठन पर भी स्थिति स्पष्ट करने को कह सकती है। पिछली सुनवाई में अदालत ने निष्पक्ष जांच और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी गठित करने की आवश्यकता जताई थी। अयोध्या के राम मंदिर में ट्रस्ट को मिले दान और चढ़ावे के प्रबंधन में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को फिर सुनवाई करेगा। मामले में उत्तर प्रदेश सरकार से विशेष जांच दल (एसआईटी) के पुनर्गठन पर अपना रुख स्पष्ट करने की भी संभावना है।



2028 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा : सिद्धारमैया का बड़ा एलान, बोले- उम्र, स्वास्थ्य और राजनीति में बढ़ता भ्रष्टाचार बनी वजह

मध्य स्वर्णिम, बंगलूरु।

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया ने रविवार को अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर बड़ा एलान किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह वर्ष 2028 में होने वाला कर्नाटक विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। सिद्धारमैया ने अपने निर्णय के पीछे बढ़ती उम्र, स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों और राजनीति में बढ़ते भ्रष्टाचार को प्रमुख कारण बताया। हालांकि उन्होंने साफ किया कि चुनावी राजनीति से दूरी बनाने के बावजूद वह सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहेंगे और जनता के मुद्दों को उभारेंगे। सिद्धारमैया ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से अपने फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में उनकी उम्र 79 वर्ष है और कर्नाटक में मौजूद सरकार का कार्यकाल करीब डेढ़ वर्ष और बाकी



है। वर्ष 2028 तक उनकी उम्र 81-82 वर्ष हो जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य अब पहले जैसा नहीं रहा है और वह पहले की तरह ऊर्जा तथा उत्साह के साथ सक्रिय राजनीतिक भूमिका निभाने की स्थिति में नहीं हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने बताया कि उनके विधानसभा क्षेत्र वरुणा के लोग लगातार उनसे एक बार फिर चुनाव लड़ने का आग्रह कर रहे हैं। इसके बावजूद उन्होंने भविष्य में कोई चुनाव नहीं लड़ने का मन बना लिया है। उन्होंने

कहा कि यह निर्णय उन्होंने काफी सोच-विचार के बाद लिया है। सिद्धारमैया ने अपने लंबे राजनीतिक सफर को याद करते हुए कहा कि उन्होंने वर्ष 1978 में तालुक बोर्ड सदस्य के रूप में राजनीति में प्रवेश किया था। वर्ष 2028 में उनके सार्वजनिक जीवन के 50 वर्ष पूरे हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने जीत और हार दोनों का सामना किया, लेकिन उन्हें इस बात का संतोष है कि उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया और न ही अपनी अंतर्गता के विरुद्ध कोई काम किया। सिद्धारमैया ने अपने चुनावी राजनीति से दूर होने के फैसले के पीछे राजनीति में बढ़ते भ्रष्टाचार को भी एक अहम कारण बताया। मांड्या जिले में एक निजी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने चुनावी राजनीति में बढ़ते धनबल पर चिंता व्यक्त की।



जिसमें सीजेपी के प्रदर्शन को विदेशी फंडिंग से मुक्त होने की बात कही गई हो। विदेश मंत्रालय की फैक्ट चेक इकाई ने अपने आधिकारिक पोस्ट में कहा कि वायरल पोस्ट भ्रामक है और इसमें प्रवक्ता के वास्तविक बयान को गलत संदर्भ में

क्या सीजेपी प्रदर्शन को विदेशी फंडिंग पर मिली क्लीन चिट ? विदेश मंत्रालय का फैक्ट चेक, कहा- वायरल पोस्ट भ्रामक

मध्य स्वर्णिम, नई दिल्ली।

नीट-यूजी 2026 पेपर लीक के विरोध में चले सीजेपी प्रदर्शन को कथित विदेशी फंडिंग मिलने के दावे को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक पोस्ट को विदेश मंत्रालय ने भ्रामक बताया है। मंत्रालय की फैक्ट चेक इकाई ने रविवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट जारी कर स्पष्ट किया कि वायरल पोस्ट में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि प्रवक्ता ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था,

प्रस्तुत किया गया है। मंत्रालय के अनुसार, वायरल संदेश में प्रवक्ता के बयान के साथ एक ऐसा कथन जोड़ दिया गया, जो आधिकारिक ब्रीफिंग के दौरान उनके द्वारा कहा ही नहीं गया था। सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट में दावा किया गया था कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से सीजेपी के प्रदर्शन के लिए विदेशी फंडिंग के बारे में कई बार सवाल पूछा गया था और उन्होंने कथित तौर पर कहा कि भारतीय खुफिया एवं जांच एजेंसियों की जांच में प्रदर्शन के लिए किसी तरह की विदेशी फंडिंग नहीं मिली है।

अवैध कोयला खनन पर सीआईएसएफ का बड़ा एक्शन

नई दिल्ली। अवैध कोयला खनन, चोरी और अनधिकृत परिवहन के खिलाफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने देशभर में अपना अभियान तेज कर दिया है। गृह मंत्रालय के निर्देशों के तहत चलाए जा रहे इस अभियान में सीआईएसएफ ने महज एक सप्ताह के दौरान विभिन्न कोयला कंपनियों के क्षेत्रों में खुफिया जानकारी के आधार पर 85 छापेमारी की। इन कार्रवाइयों में



1277 मीट्रिक टन अवैध रूप से खनन और परिवहन किया गया कोयला जब्त किया गया है।सीआईएसएफ की ओर से 20 जुलाई से 26 जुलाई के बीच की गई कार्रवाई के दौरान अवैध कोयला कारोबार से जुड़े पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 40 वाहनों को भी जब्त किया गया है। इस दौरान एक प्राथमिकी भी दर्ज की गई।

एंकर

पेपर लीक विरोधी बिल पर संसद में तीखी बहस की तैयारी

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी नहीं थमा गतिरोध, अब पीएम मोदी से माफी की मांग पर अड़ा विपक्ष

मध्य स्वर्णिम, नई दिल्ली।

नीट पेपर लीक विवाद को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। विपक्ष ने अब छात्रों पर कथित पुलिस बर्बरता और जंतर-मंतर पर हुए घटनाक्रम को मुद्दा बनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग तेज कर दी है। विपक्ष का आरोप है कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ ज़रूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया गया और इस पूरे मामले की जिम्मेदारी तय कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को कांग्रेस और विपक्ष दल छात्रों के आंदोलन की बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रहे हैं। हालांकि, विपक्ष का कहना है कि केवल



को लेकर जवाब देना होगा। विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी से माफी मांगने के साथ-साथ उन अधिकारियों और सुरक्षाकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जिन पर प्रदर्शनकारियों के साथ कथित तौर पर ज़्यादाती करने के आरोप लगे हैं। लोकसभा में

नेता विपक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कथित कार्रवाई को लेकर जवाबदेही तय करने की मांग की है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पैलेट गन या अन्य जानलेवा बल के इस्तेमाल की अनुमति दी गई थी। राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन नागरिकों का अधिकार है और सरकार की जिम्मेदारी है कि वह प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे तथा उनकी शिकायतों का वातचीत के जरिए समाधान निकाले। विपक्ष का आरोप है कि जंतर-मंतर पर छात्रों के आंदोलन के दौरान जिस तरह की कार्रवाई हुई, उससे कई गंभीर सवाल खड़े हुए हैं।

कांग्रेस बोली- शिक्षा मंत्री के बाद अब प्रधानमंत्री की बारी

■ विपक्ष अब इस पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग कर रहा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि छात्रों के भविष्य से जुड़े इतने गंभीर मुद्दे पर सरकार को संवेदनशीलता के साथ कदम उठाना चाहिए था। कांग्रेस ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को छात्रों की जीत बताया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे सहित अन्य नेताओं ने कहा कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सामने आकर छात्रों से माफी मांगनी चाहिए। विपक्ष का आरोप है कि नीट पेपर लीक से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ और इसके बाद विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ कथित तौर पर बल प्रयोग किया गया। खरगे ने कहा कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठी, डंडे और कथित पैलेट गन के इस्तेमाल के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।



पैलेट गन के इस्तेमाल की इजाजत किसने दी ? राहुल गांधी ने अमित शाह को चिट्ठी लिखकर मांगा जवाब

मध्य स्वर्णिम, नई दिल्ली।

नीट पेपर लीक के विरोध में 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई और पैलेट गन के इस्तेमाल का मामला अब राजनीतिक रूप से गरमा गया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर पूरे घटनाक्रम की जवाबदेही तय करने की मांग की है। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पैलेट गन जैसे हथियारों के इस्तेमाल की अनुमति आखिर किसने दी थी। राहुल गांधी ने अपने पत्र में दावा किया कि प्रदर्शन के दौरान कथित पैलेट गन की कार्रवाई में एक 19 वर्षीय छात्र गंभीर रूप से घायल हुआ है और उसकी एक आंख की रक्षा भी खतरा बताया जा रहा है। उन्होंने गृह मंत्री से इस पूरे मामले में स्पष्ट जवाब देने की मांग की है। राहुल गांधी ने अमित शाह को लिखे पत्र में कहा कि दिल्ली में तैनात सुरक्षा बल गृह मंत्रालय के प्रति जवाबदेह हैं। ऐसे में उन्होंने पूछा कि क्या गृह मंत्री के तौर पर उन्होंने छात्रों के खिलाफ पैलेट गन समेत किसी

भी तरह के जानलेवा बल के इस्तेमाल की मंजूरी दी थी? यदि नहीं, तो इस कार्रवाई की अनुमति किस अधिकारी या किस स्तर पर दी गई? उन्होंने दूसरा सवाल सादे कपड़ों में कथित रूप से छात्रों पर लाठी चलाने वाले लोगों को लेकर उठाया। राहुल गांधी ने पूछा कि प्रदर्शन के दौरान सादे कपड़ों में छात्रों को पीटते हुए दिखाई देने वाले लोग कौन थे? क्या वे पुलिसकर्मी थे या किसी अन्य संगठन के स्वयंसेवक? उनकी तैनाती की अनुमति किसने दी थी? कांग्रेस नेता ने अपने पत्र में कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन का महत्वपूर्ण स्थान है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे और उनकी शिकायतों का वातचीत के जरिए समाधान निकाले। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि छात्रों के साथ हुई कथित हिंसक कार्रवाई लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। उन्होंने कहा कि देश के युवा और छात्र अपने भविष्य को लेकर जवाब और जवाबदेही मांग रहे हैं। उनके मुताबिक, नीट पेपर लीक जैसे मामले ने लाखों छात्रों और उनके परिवारों को प्रभावित किया है।

स्कूली बच्चों के अवैध परिवहन पर आरटीओ का विशेष अभियान, चार वाहन जब्त



तीन मारुति ओमनी वैन और एक ऑटो रिक्शा पर कार्रवाई; नियमों के उल्लंघन पर 23 हजार रुपए का जुर्माना वसूला

मध्य स्वर्णिम, इंदौर।

स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने शनिवार सुबह शहर में विशेष जांच अभियान चलाया। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशानुसार संभागीय सड़क सुरक्षा दस्ता और आरटीओ इंदौर की संयुक्त टीम ने विभिन्न विद्यालय मार्गों पर पहुंचकर स्कूल वाहनों की सघन जांच की। अभियान के दौरान बच्चों के अवैध एवं असुरक्षित परिवहन के मामलों को लेकर कार्रवाई की गई। जांच के दौरान नियमों

का उल्लंघन पाए जाने पर तीन मारुति ओमनी वैन और एक ऑटो रिक्शा को जब्त किया गया। वहीं मोटरयान अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले वाहन संचालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करते हुए कुल 23 हजार रुपए का जुर्माना वसूला गया। आरटीओ इंदौर प्रदीप शर्मा के मार्गदर्शन में संभागीय सड़क सुरक्षा दस्ता प्रभारी परिवहन निरीक्षक आकाश सिटोले के नेतृत्व में टीम ने शहर के विभिन्न स्कूल मार्गों पर जांच की। अभियान के

दौरान मारुति वैन, ऑटो रिक्शा और स्कूल बसों को रोककर उनके दस्तावेज, फिटनेस, परमिट और सुरक्षा मानकों की जांच की गई। अधिकारियों ने यह भी देखा कि स्कूली बच्चों को ले जाने वाले वाहनों में निर्धारित क्षमता के अनुरूप ही बच्चों का परिवहन किया जा रहा है या नहीं। इसके साथ ही वाहन चालकों द्वारा आवश्यक नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं, इसकी भी जांच की गई परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि स्कूली बच्चों को

लाने-ले जाने वाले वाहनों की सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्षमता से अधिक बच्चों को वाहन में बैठकर परिवहन करना बच्चों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। ऐसे वाहनों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। अधिकारियों ने कहा कि कई बार स्कूल आने-जाने के लिए छोटे वाहनों का उपयोग किया जाता है। ऐसे में वाहन की क्षमता, फिटनेस और सुरक्षा व्यवस्था का पालन बेहद जरूरी है।

न्यूज़ बीफ

किराए के कमरे में युवती का जला हुआ शव मिला

इंदौर। इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में 26 वर्षीय युवती का घर में दो दिन पुराना जला हुआ शव मिला है। शव पूरी तरह झुलसा हुआ था। आसपास के रहवासियों ने दरवाजा तोड़ा, तब घटना की जानकारी मिली और पुलिस को सूचना दी। पुलिस के मुताबिक, तपेश्वरी बाग निवासी पलक केशव का शव मिला है। वह यहां किराए के कमरे में रहती थी। मूल रूप से वह टिमरनी, जिला हरदा की रहने वाली थी। फिलहाल घटना का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस आत्महत्या और हत्या, दोनों बिंदुओं पर जांच कर रही है। युवती का शव किचन में मिला है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पिता दो दिन से युवती को फोन लगा रहे थे, लेकिन वह फोन नहीं उठा रही थी। इसके बाद पिता ने मकान मालिक को फोन किया। मकान मालिक ने आसपास के लोगों की मदद से दरवाजा तोड़कर देखा तो घटना का पता चला। युवती बिजनेस पार्क स्थित एक बैंक में काम करती थी। पुलिस जब जांच के लिए पहुंची तो किचन में गैस बर्नर खुला मिला। शव करीब दो दिन पुराना बताया जा रहा है। वह छोटे गैस सिलेंडर का उपयोग करती थी। घटना की सूचना मिलने के बाद हरदा से परिवार इंदौर के लिए रवाना हो गया है। पुलिस ने मार्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। युवती के सिर में चोट के निशान भी मिले हैं। एफएसएल जांच के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा।

शराब पीकर कार चला रहे युवकों ने पुलिसकर्मियों से की मारपीट

इंदौर। इंदौर के कनाड़िया में चेकिंग के दौरान तीन पुलिसकर्मियों की पिटाई हो गई। कार सवारों को पुलिसकर्मियों ने पकड़ा तो उन्होंने पुलिसकर्मियों से जमकर मारपीट कर दी। मामला अधिकारियों तक पहुंचा, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई। कुछ दिनों पहले जमीनी विवाद में भी यहां पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया था। कनाड़िया पुलिस ने राहुल गेहलोद निवासी कृष्ण बाग कॉलोनी, सुभाष चौधान, आशीष और संतोष के खिलाफ शराब पीकर कार चलाने और पुलिसकर्मियों से विवाद कर मारपीट करने के मामले में एफआईआर दर्ज की है। पुलिस के मुताबिक, शनिवार-रविवार की दरमियानी रात करीब 2 बजे मुकाम सिंह डबार थाने के अन्य पुलिसकर्मी किशोर सावलिया, विजय यादव, रूपेंद्र भाटी, ओमप्रकाश, मुकेश व अन्य के साथ शराब पीकर वाहन चलाने वालों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान कार नंबर M P132K1644 लेकर राहुल गेहलोद वहां पहुंचा। कार में उसके अन्य साथी भी थे। अधिक शराब पीने के चलते राहुल गेहलोद का चालान बनाया गया, जिस पर सभी पुलिस से विवाद करने लगे। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने कार को थाने ले जाने की बात कही। तब राहुल और उसके साथियों ने हाथपाई कर दी। साथ ही अपशब्द कहते हुए नौकरी छिनवाने की धमकी दी। इस दौरान पुलिसकर्मी अशोक, किशोर सावलिया और विजय यादव के साथ जमकर मारपीट की गई, जिसमें तीनों के चेहरे और हाथ में चोट आई।



नीचे सड़क, ऊपर मेट्रो ट्रैक; लवकुश चौराहे की एक लेन शुरू, दूसरी सितंबर तक होगी तैयार

इंदौर में तैयार हो रहा एमपी का पहला डबल डेकर ब्रिज, नीचे सड़क ऊपर दौड़ेगी मेट्रो



मध्य स्वर्णिम, इंदौर।

शहर के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण चौराहों में शामिल लवकुश चौराहा अब आधुनिक यातायात व्यवस्था के एक बड़े केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। करीब 175 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा प्रदेश का पहला डबल डेकर ब्रिज अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। इस परियोजना की एक लेन का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कर चुके हैं, जिससे लवकुश चौराहे के आसपास यातायात का दबाव कम करने में मदद मिलने लगी है। दूसरी लेन का निर्माण भी तेजी से जारी है और इसे सितंबर 2026 तक शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। इस डबल डेकर ब्रिज की सबसे खास बात यह है कि एक ही मार्ग पर परिवहन की दो अलग-अलग व्यवस्थाएं अलग-अलग स्तर पर संचालित होंगी। नीचे सड़क यातायात चलेगा, जबकि ऊपर मेट्रो रेल का ट्रैक होगा। सीमित स्थान में सड़क और मेट्रो की सुविधा को एक साथ विकसित करने वाली यह परियोजना इंदौर के साथ-साथ पूरे प्रदेश के लिए

इंदौर-उज्जैन के बीच सफर होगा और आसान

■ लवकुश चौराहे पर बन रहा यह डबल डेकर ब्रिज मध्य प्रदेश में अपनी तरह की पहली परियोजना है। इसमें नीचे सड़क यातायात और ऊपर मेट्रो रेल का संचालन प्रस्तावित है। दोनों परिवहन व्यवस्थाओं को एक ही कॉरिडोर में अलग-अलग स्तर पर विकसित करने से जमीन की आवश्यकता कम होगी और उपलब्ध स्थान का बेहतर उपयोग किया जा सकेगा।

2023 में शुरू हुआ था निर्माण

इंदौर विकास प्राधिकरण यानी आईडीए ने इस महत्वपूर्ण परियोजना का निर्माण वर्ष 2023 में शुरू कराया था। परियोजना के निर्माण के दौरान मेट्रो कॉरिडोर के साथ समन्वय, तकनीकी जटिलताओं और स्टील बो-रिफ्टिंग ढांचे के निर्माण के कारण काम को अलग-अलग चरणों में पूरा किया गया।



महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ब्रिज की दोनों लेन पूरी तरह शुरू होने के बाद उज्जैन रोड, एमआर-10, बाणगंगा, अरबिंदो अस्पताल, एयरपोर्ट और शहर के पश्चिमी हिस्से के बीच आने-जाने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इससे शहर के प्रमुख मार्गों पर यातायात का

दबाव कम होगा और यात्रियों को पहले की तुलना में कम समय में अपने गंतव्य तक पहुंचने में मदद मिलेगी। यह परियोजना एमआर-10 रोड पर यातायात व्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही आने वाले वर्षों में इंदौर के बढ़ते शहरी विस्तार और यातायात जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार, शहर में वाहनों की संख्या लगातार बढ़ने के बीच ऐसे बहुस्तरीय परिवहन ढांचे की आवश्यकता भविष्य में और बढ़ेगी।

इंदौर-उज्जैन क्षेत्रीय विकास को मिलेगी रफ्तार

ब्रिज के पूरी तरह शुरू होने के बाद उज्जैन रोड पर वाहनों का दबाव कम होने की उम्मीद है। एयरपोर्ट से उज्जैन के बीच बेहतर संपर्क सुविधा विकसित होगी। इसके साथ ही बाणगंगा, एमआर-10 और अरबिंदो अस्पताल क्षेत्र में यातायात के दबाव को नियंत्रित करने में भी मदद मिल सकती है। यातायात

के सुचारु होने से यात्रियों के समय और ईंधन दोनों की बचत होने की संभावना है। खासतौर पर रोजाना इस मार्ग से आने-जाने वाले लोगों को इसका सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। राज्य सरकार इंदौर-

उज्जैन मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी इंदौर-उज्जैन महानगरीय क्षेत्र विकसित करने की दिशा में भी काम कर रही है। इसका उद्देश्य दोनों शहरों को आर्थिक, औद्योगिक, आवासीय और परिवहन नेटवर्क के माध्यम से एक-दूसरे से बेहतर

तरीके से जोड़ना है। ऐसे में लवकुश डबल डेकर ब्रिज को इस क्षेत्रीय विकास की महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है। बेहतर सड़क संपर्क और मेट्रो कनेक्टिविटी के साथ आने वाले समय में औद्योगिक निवेश, आवासीय विकास और माल परिवहन व्यवस्था को भी गति मिलने की उम्मीद है।



मंत्री विजयवर्गीय बोले- कांग्रेस अवसरवाद की राजनीति कर रही, छात्र आंदोलन से उसका कोई लेना-देना नहीं

मध्य स्वर्णिम, इंदौर।

नीट परीक्षा को लेकर चल रहे विवाद और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस की ओर से निकाले गए विरोध जुलूस पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कांग्रेस पर राजनीतिक अवसरवाद की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जिस आंदोलन को लेकर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है, उससे उसका वास्तविक रूप से कोई लेना-देना नहीं है। उनके अनुसार, पहले छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया और पुलिस की कार्रवाई भी हुई, लेकिन बाद में कांग्रेस ने राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से इस मुद्दे को अपने हाथ में लेने की कोशिश की। मंत्री विजयवर्गीय ने यह बात शनिवार रात इंदौर में कांग्रेस द्वारा धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफा रत इंदौर में कांग्रेस द्वारा धर्मेन्द्र प्रधान के जुलूस पर प्रतिक्रिया देते हुए कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हर उस मुद्दे में राजनीतिक अवसर दिखाई देता है, जिससे उसे सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का मौका मिल सके। उन्होंने कांग्रेस की भूमिका को अवसरवाद की राजनीति बताते



हुए कहा कि जिस आंदोलन का मूल उद्देश्य छात्रों की समस्याओं और परीक्षा व्यवस्था से जुड़े सबालों को उठाना था, उसमें कांग्रेस बाद में राजनीतिक लाभ लेने के लिए शामिल हुई। विजयवर्गीय ने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत छात्रों के आंदोलन से हुई थी। छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और इसी दौरान पुलिस की कार्रवाई भी हुई। उनका कहना

मुद्दे के माध्यम से राजनीतिक लाभ लिया जा सकता है, तब उसने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने कांग्रेस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि विपक्ष को हर घटना को राजनीतिक रंग देने के बजाय वास्तविक मुद्दों पर गंभीरता से बात करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का इस पूरे घटनाक्रम में कोई वास्तविक योगदान नहीं था और अब वह केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए आंदोलन का समर्थन कर रही है।

बंगाल चुनाव के बाद विपक्ष निराश था

■ मंत्री ने तर्ज कसते हुए कहा कि यदि पड़ोसी के घर बच्चा पैदा हो जाए और कांग्रेस डील बजाने लगे, तो उसमें कांग्रेस की क्या भूमिका होगी। उन्होंने इसी उदाहरण के माध्यम से कांग्रेस पर दूसरे के मुद्दे को राजनीतिक अवसर के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। विजयवर्गीय ने कहा कि बंगाल चुनाव के बाद विपक्ष पूरी तरह निराश हो चुका था और उसे सरकार के खिलाफ राजनीति करने के लिए एक नए मुद्दे की तलाश थी। उनके अनुसार,



जैसे ही नीट परीक्षा से जुड़ा विवाद सामने आया, विपक्ष को इसमें राजनीतिक संभावना नजर आने लगी। उन्होंने कहा कि छात्रों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए और परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता को लेकर यदि किसी प्रकार की शिकायत है तो उसकी निष्पक्ष जांच भी जरूरी है। लेकिन किसी छात्र आंदोलन को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करना उचित नहीं है।

शहरवासियों ने लिया नशामुक्त इंदौर का संकल्प

स्टेडियम से निकली नशामुक्ति मैराथन रजत पाटीदार ने युवाओं को किया प्रेरित

मध्य स्वर्णिम, इंदौर।

नशे के खिलाफ जनजागरूकता बढ़ाने और युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से दूर रखने के उद्देश्य से इंदौर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से रविवार सुबह नेहरू स्टेडियम से जागरूकता मैराथन का आयोजन किया गया। नशे से दूरी है जरूरी 2.0 से नो ड्रग्स अभियान के तहत आयोजित इस मैराथन में भारतीय क्रिकेटर रजत पाटीदार सहित बड़ी संख्या में युवाओं, विद्यार्थियों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों और शहरवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सुबह से ही नेहरू स्टेडियम में मैराथन में शामिल होने वाले प्रतिभागियों का पहुंचना शुरू हो गया था। युवाओं में आयोजन को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। प्रतिभागियों ने नशे के खिलाफ जागरूकता संदेश लिखी तख्तियां हाथों में लेकर लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। मैराथन के दौरान प्रतिभागियों ने नशामुक्त समाज के समर्थन में नारे लगाए और स्वास्थ्य एवं सकारात्मक जीवनशैली अपनाने का संकल्प लिया। मैराथन का मुख्य उद्देश्य युवाओं और

आमजन को नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले शारीरिक, मानसिक और सामाजिक नुकसान के प्रति जागरूक करना था। पुलिस की ओर से आयोजित इस अभियान के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया गया कि नशे की आदत न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, बल्कि उसके परिवार, शिक्षा, करियर और सामाजिक जीवन पर भी गंभीर असर डाल सकती है। मैराथन में शामिल युवाओं ने दौड़ के माध्यम से लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और नशे से पूरी तरह दूरी बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। आयोजन के दौरान युवाओं की सक्रिय भागीदारी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। विद्यार्थियों और युवा प्रतिभागियों ने उत्साह के साथ मैराथन में हिस्सा लेकर नशामुक्त समाज बनाने का संदेश दिया। मैराथन के अवसर पर भारतीय क्रिकेटर रजत पाटीदार ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि यदि जीवन में सफलता हासिल करनी है और अपने सपनों को पूरा करना है तो नशे से दूर रहना बेहद जरूरी है।



नैतिकता नहीं,भारी युवा आक्रोश के चलते हुआ शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा छात्रों व युवाओं का आंदोलन अभी लगभग पूरे देश में फैलता ही जा रहा था कि गत शनिवार सरकार को उन्हें पद से हटाना ही पड़ गया। आंदोलित छात्रों को केवल विपक्ष या अन्य तमाम समेलिब्रटीज का ही समर्थन नहीं मिला बल्कि उन्हें भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री मुरली मनोहर जोशी का भी समर्थन हासिल हुआ। जोशी ने छात्र आंदोलन को अपना समर्थन देते हुये कहा था कि महिलाओं और कम उम्र की लड़कियों के साथ बेहमी से बुरा व्यवहार किया गया, जिससे उन्हें गहरा दुख हुआ। उन्होंने कहा कि छात्र कई दिनों से नई दिल्ली की सड़कों पर हैं और उनकी चिंताएँ वाजिब हैं, जिनका समाधान सहानुभूति और संवाद के माध्यम से होना चाहिए था, न कि केवल कानून-व्यवस्था का मामला मानकर बल प्रयोग से। परन्तु अहंकारी सत्ता ने समय रहते शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की उनकी मांग पूरी करने के बजाय पुलिस बल का प्रयोग कर उन्हें भयभीत करने की रणनीति अपनाई। और आखिरकार पुलिस की दमनकारी नीति सरकार को और भारी पड़ गयी।

सवाल यह है कि जिस धर्मेंद्र प्रधान के जुलाई 2021 से जुलाई 2026 तक के शिक्षा मंत्री के कार्यकाल के दौरान देश में अलग-अलग स्तरों पर लगभग 70 से 80 बार पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। जिस धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री मंत्री रहते विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं (विशेषकर NEET और UGC-NET) में हुई पेपर लीक की घटनाओं और उनके मानसिक तनाव के कारण और उसके बाद उनके भविष्य को लेकर पैदा हुई अनिश्चितता के चलते पिछले कुछ हफ्तों में ही 21 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। और देश के करोड़ों छात्रों का भविष्य सीधे तौर पर प्रभावित हुआ, केवल नीट परीक्षा के पेपर लीक, परिणाम रह होने और री-टेस्ट के कारण अकेले 22 लाख से अधिक (2.2 मिलियन) छात्रों का भविष्य अध्र में लटक गया और उन्हें दोबारा भीषण मानसिक तनाव में परीक्षा की तैयारी करनी पड़ी। इसी तरह यूजीसी-नेट परीक्षा, डाकॅ नेट पर पेपर लीक होने की वजह से रातों-रात परीक्षा रद्द होने के कारण 9 लाख से अधिक छात्रों का कैरियर सीधे प्रभावित हुआ। ऐसे शिक्षा मंत्री को हटाने में सरकार को आखिर इतना समय क्यों लगा।

दरअसल धर्मेंद्र प्रधान बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा और उसकी सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों से गहराई से जुड़े रहे हैं। उनका पूरा राजनीतिक और सामाजिक आधार संघ से ही प्रेरित रहा है। धर्मेंद्र प्रधान के पिता डॉ. देवेंद्र प्रधान ओडिशा में भाजपा के शुरुआती नेताओं में से थे और स्वयं संघ के आजीवन कार्यकर्ता रहे। डॉ. देवेंद्र प्रधान 199८-2004 के मध्य वाजपेयी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहे। जुलाई 2021 में जब धर्मेंद्र प्रधान को केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद की जिम्मेदारी दी गई, तो उन्होंने देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) को लागू करने पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया। इस दौरान उन्होंने पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा कर भारतीय महापुरुषों और स्वदेशी इतिहास को प्रमुखता से शामिल करने का कार्य किया, जिसे संघ के सांस्कृतिक और शैक्षिक दृष्टिकोण के अनुकूल माना जाता है।

धर्मेंद्र प्रधान की सारी शक्ती रहते हुए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) और नए नेशनल Curriculum फ्रेम वर्क (NCF-SE 2023) के तहत स्कूली पाठ्यक्रमों (विशेषकर NCERT किताबों) में व्यापक बदलाव किए गए। इसमें वेदों, प्राचीन भारतीय ग्रंथों, पारंपरिक ज्ञान, प्राचीन खगोल विज्ञान और भारत की समृद्ध गणितीय विरासत (जैसे प्राचीन गणितज्ञों के योगदान) से जुड़े संदर्भों को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। कक्षा 6 से ही कोडिंग, वित्तीय साक्षरता,कृत्रिम बुद्धिमता, और स्थानीय शिल्पकला (जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, बागवानी आदि) जैसे व्यावहारिक विषयों को मुख्य पाठ्यक्रम में जोड़ा गया। स्कूली स्तर पर स्वास्थ्य, कल्याण और योग को शारीरिक शिक्षा के अनिवार्य और मुख्य मूल्यांकन का हिस्सा बनाया गया। इसी तरह NCERT की कक्षा 6 से 12वीं तक की किताबों से पाठ्यक्रम का लगभग 30% हिस्सा हटा दिया गया, जिसे लेकर काफी विवाद भी हुआ। इतिहास की किताबों (विशेषकर कक्षा 12वीं) से मुगल शासक, मुगल शासकों के इतिहास और उनके प्रशासनिक तौर-तरीकों से जुड़े कुछ विस्तृत अध्यायों और अंशों को हटाया या छोटा किया गया। सामाजिक विज्ञान की किताबों से 2002 के गुजरात दंगे, देश में लागू हुआ आपातकाल, नक्सली आंदोलन और शीत युद्ध के दौर से जुड़े कई महत्वपूर्ण संदर्भों और अध्यायों को पूरी तरह हटा दिया गया। कक्षा 9वीं और 10वीं की विज्ञान की किताबों से जीवों के विकास के सिद्धांत यानी डार्विन का सिद्धांत और आवर्त सारणी के कुछ बुनियादी अध्यायों को मुख्य पाठ्यक्रम से हटाया गया।

कक्षा 10वीं के नानािक शास्त्र से लोकतंत्र और विविधता, लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन तथा लोकतंत्र की चुनौतियां जैसे अध्यायों को पाठ्यक्रम से बाहर किया गया। उस समय शिक्षा मंत्रालय और रूष्ट्रध्वज्ज ने इन बदलावों पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा था कि यह बदलाव विशेषज्ञों के विचार, विभिन्न स्तरों पर पाठों के दोहराव को रोकने और छात्रों को आधुनिक समय की ज़रूरतों के अनुरूप तैयार करने के लिए किए गए हैं, न कि किसी राजनीतिक एजेंडे के तहत। शायद यही वजह थी कि संघ के एजेंडे को लागू करने वाली नई शिक्षा नीति के कार्यान्वन के मध्य सरकार प्रधान को हटाना नहीं चाह रही थी। परन्तु अब राजनीतिक गलियायों में अपृष्ठ रूप से यह चर्चा भी हो रही है कि युवा आंदोलन के मध्य संघ प्रमुख मोहन भागवत द्वारा सरकार को युवाओं के साथ संवाद और संवेदनशीलता बरतने के दिए गए।

सौ दो सौ बूंदें टपका कर कंहा गायब हो गए प्यारे मानसून

वैतन्य भद्र
गर्मी, गर्मी, गर्मी, हाय गर्मी लोग मरे जा रहे है गर्मी से, सूर्य देवता भी अपनी पूरी ताकत लगाए पड़े हैं कि कितनी गर्मी धरती पर बरसा दें, जनता पसीने से भीग चुकी है,कैचुर, एसी सब फेल हो चुके हैं पतियों तालियों का पानी सूख गया है बस इंतजार है तो मानसून के बादलों का लेकिन मानसून देखो तो इस तरफ नजर इनायत नहीं कर रहा। वंही दूसरी तरफ मुंबई नजर, सूरत हो, अहमदाबाद हो ऐसा बरसा कि शहर समुद्र नजर आने लग रहा लेकिन पता नहीं मध्यप्रदेश से क्या खुदक हो गई है कि इस तरफ झाँक भी नहीं रहा । रोजाना मौसम विभाग वाले भविष्यवाणी करते है कि बस इंतजार की घड़ियाँ खत्म हुई बादल ऐसे बरसेंगे कि भागते गैल नहीं मिलेंगे लेकिन हुवा क्या है दस पचास बूंदे टपका कर गायब हो जाते हैं ये बादल ।

अपन ने तो ये सुना था मुंबई से तुम सीधे जबलपुर आते हो यानी मध्यप्रदेश में प्रवेश कर लेते हो लेकिन ये भी नहीं हो रहा ,वैसे तुम्हारा पुराना रिकॉर्ड भटकने का रहा है अपने को तो एक बात आज तक समझ में नहीं आई कि तुम हर साल आते हो तो फिर एक साल में अपना रास्ता कैसे भूल जाते हो तुम्हारे इंतजार में लोग काला चश्मा लगाकर आसमान की तरफ देख रहे लेकिन अभी दूर-दूर तक तुम्हारे बादलों का तप नही है, अगर सीधे-सीधे मुंबई से गरीब रथ में बैठ जाते या मुंबई से जबलपुर आने वाली और किसी ट्रेन से आ जाते तो दूसरे दिन ही पहुंच जाते आना होता तो सीधे-सीधे फ्लाइट से आ जाते आने के तो बहुत से रास्ते थे लेकिन लगता है तुम भी नेता

योगेश कुमार गोयल

‘मिसाइल मैन’ के नाम से विख्यात डा. एपीजे अब्दुल कलाम (अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम) भारतीय इतिहास में एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं, जो वैज्ञानिक थे। देश के महान् वैज्ञानिक होने के साथ-साथ वह एक अद्भुत ईसान और एक प्रेरणादायक नेता भी थे। सादगी, मितव्ययिता और ईमानदारी जैसे विलक्षण गुणों की मिसाल डा. कलाम ने अपने इन्हीं गुणों की बदौलत समस्त देशवासियों को दिल जीत लिया था क्योंकि मौजूदा राजनीतिक परिवेश में ऐसे गुणों वाले व्यक्ति का मिलना दुर्लभ है। यही कारण है कि करोड़ों लोग आज भी उन्हें अपना प्रेरणास्त्रोत मानते हुए उनकी कही बातों का अनुसरण करते हैं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि उन्होंने जिस भी व्यक्ति के साथ काम किया।

उसी के दिल को जीत लिया। देश की युवा पीढ़ी को संदेश देते हुए वह कहते थे कि भारत के युवा वर्ग में हिम्मत होनी चाहिए कि वह कुछ अलग सोच सके, हिम्मत हो कि वह कुछ खोज सके, ऐसे नए रास्तों पर चलने की हिम्मत हो, जो असंभव हो, उसे खोज सके और मुसीबतों को जीतकर सफलता हासिल कर सके। वह कहते थे कि आसमान की ओर देखें, हम अकेले नहीं हैं, पूरा ब्रह्माण्ड हमारा मित्र है और जो सपना देखते हुए मेहनत कर रहे हैं, उन्हें बेहतरीन फल देने का प्रयास कर रहा है। सपना सच हो, इसके लिए जरूरी है कि आप सपना देखें।

15 अक्तूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक गरीब परिवार में जन्मे अब्दुल कलाम गरीबी और कठिन परिस्थितियों के बावजूद उच्च शिक्षा प्राप्त कर

श्रावणी मेला : गंगा, शिव-लोकआस्था का अनश्वर उत्सव

भारतीय धार्मिक परंपरा में उत्तरवाहिनी गंगा को अत्यंत पवित्र और मोक्षदायिनी माना गया है। यही कारण है कि यहाँ से लिया गया गंगाजल विशेष रूप से पूजनीय माना जाता है और उसी जल से बाबा बैटनथा का अभिषेक करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। गंगा के मध्य विशाल शिला पर अवस्थित बाबा अजगैवीनाथ मंदिर इस यात्रा का आध्यात्मिक द्वार है। सदियों से श्रद्धालु यहीं जल भरकर अपनी पदयात्रा आरंभ करते हैं। नदी के बीच स्थित यह मंदिर मानो जल और जीवन, प्रकृति और पुरुष, शिव और शक्ति के शाश्वत मिलन का प्रतीक बनकर खड़ा है। गंगा की लहरें जब मंदिर की घटानों को स्पर्श करती हैं तो लगता है जैसे स्वयं प्रकृति शिव की आरती उतार रही हो।

कुमार कल्याण

भारत की सांस्कृतिक स्मृति में कुछ यात्राएँ केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचने का माध्यम नहीं होतीं, वे मनुष्य के भीतर की यात्रा का भी रूप ले लेती हैं। वे पगडंडियों पर चलती हुई संभ्र्यता की कथा कहती हैं, लोकजीवन की धड़कनों को स्पर् देती हैं और मनुष्यों को उसके मूल से जोड़ती हैं। बिहार के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज से झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम तक होने वाली श्रावणी कांवड़ यात्रा ऐसी ही एक जीवंत सांस्कृतिक परंपरा है। यह यात्रा केवल गंगाजल लेकर शिव के दरबार तक पहुँचने का अनुष्ठान नहीं, बल्कि भारतीय लोकजीवन की उस अखिल धारा का उत्सव है, जिसमें आस्था, अनुशासन, सेवा, सह-अस्तित्व और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता एक साथ प्रवाहित होती है। उत्तरवाहिनी गंगा के पवित्र जल को कांवर में भरकर वे लगभग 105 किलोमीटर की कठिन पदयात्रा तय करते हुए देवघर में बाबा बैद्यनाथ के योगतिर्लिन पर जलाभिषेक करेंगे। करोड़ों कदमों से बनती यह यात्रा भारत की सबसे बड़ी लोकआस्थाओं में से एक है, जो किसी सरकारी निमंत्रण या औपचारिक आयोजन से नहीं, बल्कि जनविश्वास की स्वाभाविक शक्ति से संचालित होती है।

श्रावण का महीना आते ही सुल्तानगंज का भूगोल बदल जाता है। गंगा के तट पर केसरिया रंग उतर आता है। दूर-दूर तक बोल बम और हर-हर महादेव का घोष गुँजे लगता है। ऐसा लगता है मानो नदी स्वयं मंत्रोच्चार कर रही हो और धरती स्वयं कवि बनकर अपनी पदयात्रा आरंभ कर रही हो। हजारों लोग एक ही उद्देश्य, एक ही संकल्प और एक ही विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। इस विराट जनसमूह में न जाति का भेद दिखाई देता है, न भाषा का, न प्रदेश का। यहीं हर व्यक्ति केवल एक पहचान से जाना जाता है—कांवरिया।

भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता यही रही है कि उसने धर्म को केवल मंदिरों की चारदीवारी तक सीमित नहीं रखा। यहाँ धर्म जीवन के व्यवहार, प्रकृति के सम्मान और समाज की साझी चेतना से जुड़ा रहा है। इसी कारण भारतीय तीर्थयात्राएँ केवल पूजा-पढ़ति नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक एकता की सबसे सशक्त अभिव्यक्तियाँ हैं। सुल्तानगंज से देवघर तक

वैज्ञानिक बने थे, जिनके नेतृत्व में भारत कई उपग्रह तथा स्वदेशी मिसाइलें बनाने में सफल हुआ और परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र भी बना। उन्होंने डीआरडीओ तथा इसरो की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम कर उन्हें सफल बनाया। अपने जीवनकाल में उन्होंने ‘विंग्स ऑफ फायर’, ‘इनाइटेड माइंड’, ‘इंडिया 2020: ए विजन फॉर न्यू मिलेनियम’ इत्यादि 30 से भी ज्यादा पुस्तकें लिखी।

1999 से 2001 के बीच वे भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार रहे तथा 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे। राष्ट्रपति बनने के बाद जब वे राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे तो उनके साथ सामान के रूप में केवल दो सूटकेस थे, जिनमें से एक में उनके कपड़े तथा दूसरे में उनकी प्रिय पुस्तकें थी। आज जहाँ नेतागण छुट्टियों पर घूमने जाने के लिए बेताब रहते हैं और संसद की कार्यवाहियों से भी गैरहाजिर रहते हैं, वहीं डा. कलाम ने राष्ट्रपति रहते अपने पूरे राजनीतिक जीवन में केवल दो छुट्टियां ली थी, एक अपने पिता के देहांत पर और दूसरी अपनी मां की मृत्यु के अवसर पर।

देश के सर्वोच्च पद पर रहते हुए कलाम साहब ने अपने कार्यकाल में सादगी, मितव्ययिता और ईमानदारी को जो मिसाल पेश की, वह आज और कहीं देखने को नहीं मिलती। ऐसा ही एक वाक्या स्मरण आता है, जब एक बार उनका पूरा परिवार (कुल 52 सदस्य) उनसे मिलने दिल्ली आया। स्टेशन से सभी को राष्ट्रपति भवन लाया गया, जहां सभी आठ दिनों तक ठहरे। उन पर खर्च हुई एक-एक पाई कलाम साहब ने अपनी जेब से खर्च की। बताया जाता है कि उन्होंने अपने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया था कि उनके

जब जेन-जी ने बदल दी राजनीति की भाषा

शिक्षा सुधार, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सरोकारों के लिए पहचाने जाने वाले वांग्चुक ने इस आंदोलन की शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक स्वरूप देने का प्रयास किया। उनके साथ बड़ी संख्या में छात्र और सामाजिक सेक्टन जुड़े। उनके समर्थन में मिजोरम सहित कई राज्यों में प्रदर्शन भी हुए, जिसने यह संकेत दिया कि यह मुद्दा किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है। इस आंदोलन ने मीडिया की भूमिका पर भी बहस छेड़ दी है। कई युवाओं का आरोप है कि मुख्यधारा के मीडिया के कुछ वर्गों ने आंदोलन को अपेक्षित महत्व नहीं दिया, जबकि सोशल मीडिया पर यह देशव्यापी चर्चा का विषय बना रहा। इससे सूचना के स्रोतों और मीडिया की विश्वसनीयता पर भी नए प्रश्न खड़े हुए हैं।

ऑल इज वेह केवल एक फिल्मी संवाद नहीं था, बल्कि एक पीढ़ी की उम्मीदों का प्रतीक बन गया था। फिल्म 3 इडियट्स में शिक्षा व्यवस्था की खामियों के खिलाफ जो संदेश दिया गया था, वही सवाल आज वास्तविक जीवन में फिर गुंज रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब पर्दे का काल्पनिक किरदार नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और देशभर के हजारों युवा जंतर-मंतर से शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। नीट सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक की घटनाओं ने देश के लाखों छात्रों के विश्वास को गहरी चोट पहुंचाई है। वर्षों की कठिन मेहनत, आर्थिक संघर्ष और भविष्य के सपनों के बीच यदि परीक्षा की निष्पक्षता पर ही सवाल उठने लगें, तो यह केवल एक परीक्षा का संकट नहीं रह जाता, बल्कि पूरे लोकतांत्रिक तंत्र की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न बन जाता है। दिल्ली के जंतर-मंतर पर शुरू हुआ यह आंदोलन धीरे-धीरे केवल पेपर लीक तक सीमित नहीं रहा। यह आंदोलन युवाओं की उस व्यापक बेचैनी का प्रतीक बन गया, जिसमें रोजगार, अवसरों की समानता, पारदर्शिता और जवाबदेही जैसे मुद्दे शामिल हैं।

आज की जेन ज़ी केवल भावनात्मक नारों से संतुष्ट नहीं होती, बल्कि वह तथ्यों, पारदर्शिता और संस्थागत सुधारों की मांग करती है। इस आंदोलन की एक विशेषता यह भी रही कि इसमें किसी राजनीतिक दल का झंडा नहीं दिखाई दिया। छात्र अपने भविष्य की सुरक्षा और निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली की मांग लेकर सड़कों पर उठे। सोशल मीडिया ने इस आंदोलन को नई ताकत दी। एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे मंचों पर युवाओं ने अपनी बात सीधे देश तक पहुंचाई। पारंपरिक मीडिया से इतर डिजिटल प्लेटफॉर्म इस आंदोलन का सबसे बड़ा

इन अतिथियों के लिए राष्ट्रपति भवन की कारें इस्तेमाल नहीं की जाएंगी और उनके खाने-पीने के सारे खर्च का विवरण भी अलग से रखा गया। आठ दिन बाद सभी के दिल्ली से वापस चले जाने पर कलाम साहब ने अपने निजी बैंक खाते से 3.52 लाख रुपये का चेक काटकर राष्ट्रपति कार्यालय को भेज दिया। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उन्होंने कभी किसी का कोई उपहार अपने पास नहीं रखा। दरअसल उनका कहना था कि उनके पिता ने उन्हें यही शिक्षा दी है कि कभी किसी का कोई उपहार स्वीकार मत करो। किसी ने एक बार उन्हें दो पैन उपहारस्वरूप दिए थे लेकिन वे भी उन्होंने राष्ट्रपति पद से विदाई के समय लौटा दिए थे।

भारत के बच्चों के भविष्य को लेकर वे चिंतित स्वर में कहते थे कि देश में प्रतिवर्ष दो करोड़ बच्चे जन्म लेते हैं, उन सभी बच्चों का क्या भविष्य होगा और जीवन में उनका क्या लक्ष्य होगा? क्या हमें उनके भविष्य के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए या हमें उन्हें उनके नसीब के सहारे छोड़ अभिजात्य वर्ग के फायदे के लिए ही काम करना चाहिए। डा. कलाम का मानना था कि यदि भारत को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मस्तिष्क वालों का देश बनाना है तो इसमें समाज के तीन लोग सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, पिता, माता और गुरु। भारत के भविष्य को लेकर उनके पास एक विजन था, जिस पर ‘इंडिया 2020’ ए विजन फॉर न्यू मिलेनियम’ नामक पुस्तक प्रकाशित हुई थी। दरअसल ‘टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन, फोरकारिस्टिंग एंड एसेसमेंट काउंसिल’ नामक एक सरकारी संगठन देश की प्रगति से जुड़ा विजन डॉक्यूमेंट तैयार करता है और 1996 में कलाम साहब इसके अध्यक्ष थे। उन्हीं की अध्यक्षता में 1996-

जब जेन-जी ने बदल दी राजनीति की भाषा

शिक्षा सुधार, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सरोकारों के लिए पहचाने जाने वाले वांग्चुक ने इस आंदोलन की शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक स्वरूप देने का प्रयास किया। उनके साथ बड़ी संख्या में छात्र और सामाजिक सेक्टन जुड़े। उनके समर्थन में मिजोरम सहित कई राज्यों में प्रदर्शन भी हुए, जिसने यह संकेत दिया कि यह मुद्दा किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है। इस आंदोलन ने मीडिया की भूमिका पर भी बहस छेड़ दी है। कई युवाओं का आरोप है कि मुख्यधारा के मीडिया के कुछ वर्गों ने आंदोलन को अपेक्षित महत्व नहीं दिया, जबकि सोशल मीडिया पर यह देशव्यापी चर्चा का विषय बना रहा। इससे सूचना के स्रोतों और मीडिया की विश्वसनीयता पर भी नए प्रश्न खड़े हुए हैं।

सौरभ जैन अंकित

ऑल इज वेह केवल एक फिल्मी संवाद नहीं था, बल्कि एक पीढ़ी की उम्मीदों का प्रतीक बन गया था। फिल्म 3 इडियट्स में शिक्षा व्यवस्था की खामियों के खिलाफ जो संदेश दिया गया था, वही सवाल आज वास्तविक जीवन में फिर गुंज रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब पर्दे का काल्पनिक किरदार नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और देशभर के हजारों युवा जंतर-मंतर से शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं।

नीट सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक की घटनाओं ने देश के लाखों छात्रों के विश्वास को गहरी चोट पहुंचाई है। वर्षों की कठिन मेहनत, आर्थिक संघर्ष और भविष्य के सपनों के बीच यदि परीक्षा की निष्पक्षता पर ही सवाल उठने लगें, तो यह केवल एक परीक्षा का संकट नहीं रह जाता, बल्कि पूरे लोकतांत्रिक तंत्र की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न बन जाता है। दिल्ली के जंतर-मंतर पर शुरू हुआ यह आंदोलन धीरे-धीरे केवल पेपर लीक तक सीमित नहीं रहा। यह आंदोलन युवाओं की उस व्यापक बेचैनी का प्रतीक बन गया, जिसमें रोजगार, अवसरों की समानता, पारदर्शिता और जवाबदेही जैसे मुद्दे शामिल हैं।

आज की जेन ज़ी केवल भावनात्मक नारों से संतुष्ट नहीं होती, बल्कि वह तथ्यों, पारदर्शिता और संस्थागत सुधारों की मांग करती है। इस आंदोलन की एक विशेषता यह भी रही कि इसमें किसी राजनीतिक दल का झंडा नहीं दिखाई दिया। छात्र अपने भविष्य की सुरक्षा और निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली की मांग लेकर सड़कों पर उठे। सोशल मीडिया ने इस आंदोलन को नई ताकत दी। एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे मंचों पर युवाओं ने अपनी बात सीधे देश तक पहुंचाई। पारंपरिक मीडिया से इतर डिजिटल प्लेटफॉर्म इस आंदोलन का सबसे बड़ा

97 में ‘विजन 2020’ डॉक्यूमेंट तैयार किया गया। उस रिपोर्ट में सरकार को कुछ सुझाव देते हुए बताया गया था कि 2020 तक भारत को क्या कुछ हासिल करने का लक्ष्य रखना चाहिए। रिपोर्ट के आधार पर कलाम साहब ने सरकार को सलाह दी थी कि देश के विकास के लिए तकनीक, विज्ञान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्र में सरकार को क्या करना चाहिए और आम नागरिक को इसमें क्या भूमिका निभानी चाहिए। उनका मानना था कि भारत 2020 तक युवाओं के योगदान की बदौलत एक विकसित देश बन जाएगा लेकिन वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर उनके सच विजन को पूरा होने में अभी बहुत लंबा समय लग सकता है।

डा. कलाम कहा करते थे कि दुनिया हमें तभी याद रखेगी, जब हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित और विकसित भारत देंगे, जो आर्थिक सम्पन्नता और सांस्कृतिक विरासत से मिला हो। उनका कहना था कि जो लोग अपने दिल से कार्य नहीं करते, वे जिंदगी में भले ही कुछ भी हासिल कर लें लेकिन वह खोखला होता है, जो उनके दिल में कड़वाहट भरता है। कलाम साहब के अनुसार जिंदगी कठिन है और आप तभी जीत सकते हैं, जब आप मनुष्य होने के अपने जन्मसिद्ध अधिकार के प्रति सजग हों। किसी व्यक्ति के जीवन में कठिनाई नहीं होगी तो उसे सफलता की खुशी का अहसास ही नहीं होगा। यह महान् विभूति 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में एक कार्यक्रम के दौरान छात्रों को सम्बोधित करते हुए अचानक दिल का दौरा पड़ने पर सदा के लिए चिरनिद्रा में लीन हो गई।

माध्यम बनकर उभरे। यही कारण है कि यह आंदोलन राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सलाहकू भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती केवल परीक्षा सुधार की नहीं, बल्कि युवाओं के विश्वास को बनाए रखने की भी है। सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए कठोर कानून, फास्ट ट्रैक अदालतों और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जैसे कदमों की घोषणा की है। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि यह पर्याप्त नहीं है और परीक्षा प्रणाली में व्यापक संस्थागत सुधार की आवश्यकता है।

इस पूरे घटनाक्रम में सोनम वांगचुक का नाम एक बार फिर चर्चा में आया। शिक्षा सुधार, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सरोकारों के लिए पहचाने जाने वाले वांग्चुक ने इस आंदोलन की शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक स्वरूप देने का प्रयास किया। उनके साथ बड़ी संख्या में छात्र और सामाजिक सेक्टन जुड़े। उनके समर्थन में मिजोरम सहित कई राज्यों में प्रदर्शन भी हुए, जिसने यह संकेत दिया कि यह मुद्दा किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है। इस आंदोलन ने मीडिया की भूमिका पर भी बहस छेड़ दी है। कई युवाओं का आरोप है कि मुख्यधारा के मीडिया के कुछ वर्गों ने आंदोलन को अपेक्षित महत्व नहीं दिया, जबकि सोशल मीडिया पर यह देशव्यापी चर्चा का विषय बना रहा। इससे सूचना के स्रोतों और मीडिया की विश्वसनीयता पर भी नए प्रश्न खड़े हुए हैं। भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा आबादी है। यदि यही युवा व्यवस्था पर भरोसा खोने लगें, तो यह किसी भी सरकार और समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है। प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता केवल प्रशासनिक मुद्दा नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और समान अवसर का प्रश्न है। इसलिए यह आवश्यक है कि जांच निष्पक्ष हो, दोषियों को कड़ी सजा मिले और ऐसी व्यवस्था विकसित की जाए, जिससे समाज में पेपर लीक जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। जंतर-मंतर का यह आंदोलन एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि आज की पीढ़ी केवल रोजगार नहीं, बल्कि ईमानदार अवसर चाहती है।

वह केवल आकाशमन नहीं, बल्कि जवाबदेही की अपेक्षा करती है। यह शासन और संस्थाएं इस संदेश को सम्य रहते समझ लें, तो यह आंदोलन केवल विरोध का प्रतीक नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था और लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास बहाल करने का अवसर भी बन सकता है। आखिरकार, किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी के विश्वास पर टिका होता है, और उस विश्वास की रक्षा करना सरकार, संस्थाओं और समाज—सभी की साझा जिम्मेदारी है।

चिंतन-मनन : सत्ता-संपदा का उन्माद

मनुष्य विचारशील प्राणी है, विवेकशील प्राणी है। उसके पास बुद्धि है, शक्ति है। वह अपनी बुद्धि का उपयोग करता है, चिंतन के हर कोण पर रुकता है, विवेक को जगाता है, शक्ति का नियोजन करता है और संसार के अन्य प्राणियों से बेहतर जीवन जीता है। जीने के लिए वह अनेक प्रकार की सुविधाओं को जुटाता है। सत्ता और संपदा ये तो ऐसे तत्व हैं, जिनका आकर्षण अधिकांश लोगों को बना रहता है। सत्ता के मूल में सेवा की भावना है और संपदा के मूल में जीवनयापन की। न सत्ता के बल पर कोई व्यक्ति बड़ा बनता है और न संपदा ही किसी को शिखर पर बिठा सकती है। जो लोग सेवा की पवित्र भावना से सत्ता के गलियारों में पांव रखते हैं और जीवनयापन के साधन के रूप में अर्थ का उपयोग करते हैं, वे सत्ता और संपदा प्राप्त करके भी कुछ अतिरिक्त अनुभव नहीं करते। सहज सादगीमय जीवन जीते हुए वे सत्ता और संपदा के द्वारा हितकारी प्रवृत्तियों में संलग्न हो जाते हैं।

कुछ लोगों की अवधारणा है कि व्यक्ति का अस्तित्व और व्यक्तित्व सत्ता और संपदा पर ही निर्भर है। इसलिए वे जैसे-तैसे इन्हें हथियाने का प्रयास करते हैं और ये हस्तगत हो जाएं तो इनका उचित-अनुचित लाभ भी उठा लेते हैं। ऐसे लोगों में न तो सेवा की भावना होती है और न ही वे उपयोगितावादी दृष्टि से अर्थ का अंशन करते हैं। इनके द्वारा अहंकार बढ़ता है और वे स्वयं को आम आदमी से बहुत बड़ा मानने लगते हैं। यहाँ से एक भेद-रेखा बनने लगती है, जो सत्ताधीश और संपत्तिशाली को दूसरे नजरिए से देखने का भारतल तैयार करती है। जिस व्यक्ति के पास सत्ता हो और संपदा हो, फिर भी उन्माद न हो; बहुत कठिन बात है। इन दोनों में से एक पर अधिकार पाने वाला व्यक्ति भी मूढ़ हो सकता है। जहाँ दोनों का योग हो जाए, वहां मूढ़ता न आए, यह तो संभव ही नहीं है। इस बात को सब लोग जानते हैं, फिर भी सत्ता और संपदा पाने की आकांक्षा का संवरण नहीं होता। जिनकी आकांक्षा पूरी हो जाती है।

^[1] स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक राकेश व्यास द्वारा आरडी प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स प्रा. लि., बी-48, सेक्टर 8 नोएडा, गौतम बुद्ध नगर उत्तरप्रदेश - 201301 से मुद्रित एवं बी-4, गली नं. 2 जगतपुरी कृष्णा नगर ईस्ट, नई दिल्ली-110051 से प्रकाशित।
प्रधान संपादक राकेश व्यास,
मो : - 09977701999, समूह संपादक सुनील दत्त तिवारी,
मो - 9713 289999, संपादक- ऋषिकान्त सिंह (रजत) परिहार ,
मो :- 09425002527,
स्थानीय संपादक-हितेश चिंदल *
मो :- 8708040660,
ईमेल आईडी : madhyaswarnin@gmail.com
समाचार चवन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार होंगे।
आरएनआई क्रमांक:- DLJHN/25/A5027

गुरु पूर्णिमा पर उज्जैन में सजेगा महर्षि संदीपनी गुरु पर्व का भव्य मंच

29 जुलाई को गीता भवन में होगा राज्य स्तरीय आयोजन, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव होंगे मुख्य अतिथि

मध्य स्वर्णिम, उज्जैन।

गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर उज्जैन में राज्य स्तरीय महर्षि संदीपनी गुरु पर्व का भव्य आयोजन किया जाएगा। आगामी 29 जुलाई को गीता भवन में आयोजित होने वाले इस समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थी, शिक्षक, जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर शनिवार को कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर श्री रौशन कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में आयोजन की रूपरेखा, मंच व्यवस्था, विद्यार्थियों की उपस्थिति,

सांस्कृतिक कार्यक्रमों सहित विभिन्न विभागों को सौंपी जाने वाली जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि महर्षि संदीपनी गुरु पर्व के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेंगी। इसके साथ ही विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण भी किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा, खेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। विद्यार्थियों की उपलब्धियों को मंच से प्रोत्साहित करते हुए उन्हें सम्मान प्रदान किया जाएगा, ताकि अन्य छात्र-छात्राओं को भी बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरणा मिल सके। कलेक्टर श्री रौशन कुमार सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी विद्यार्थी निर्धारित गणवेश में ही उपस्थित हों। उन्होंने विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था, कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम की गरिमा और महत्व को ध्यान में रखते हुए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्यक्रम से जुड़ी सभी तैयारियां निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरी कर ली जाएं, ताकि आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार की

अव्यवस्था न हो। बैठक में कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को लेकर विभिन्न विभागों की जिम्मेदारियों पर भी चर्चा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि आयोजन स्थल पर आवश्यक व्यवस्थाओं की समय रहते समीक्षा कर ली जाए और सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाए। कार्यक्रम में शामिल होने वाले विद्यार्थियों, शिक्षकों, जनप्रतिनिधियों और आमंत्रित अतिथियों के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि आयोजन को गरिमामय और सफल बनाने के लिए सभी विभाग पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें।

टीबी मरीजों की मदद के लिए निक्षय मित्र बनाने और आयुष्मान कार्ड शिविरों के प्रचार पर दिया जोर

जिला पंचायत की साधारण सभा में योजनाओं की समीक्षा, स्वास्थ्य और जल जीवन मिशन पर जोर

मध्य स्वर्णिम, उज्जैन।

जिला पंचायत उज्जैन की साधारण सभा की बैठक शुक्रवार को जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कमला कुंवर अंतर सिंह देवड़ा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में जिले में संचालित विभिन्न विभागीय योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जल जीवन मिशन, शिक्षा, उद्योगिकी, सहकारिता, आदिम जाति कल्याण, जिला उद्योग केंद्र, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सहित विभिन्न विभागों से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती शिवानी कुंवर सहित जिला पंचायत के सदस्य और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की जानकारी लेने के साथ ही अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने और विकास कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री श्रेयांस कुमट ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनप्रतिनिधियों से नियमित समन्वय स्थापित किया जाए। उनके क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी आवश्यकताओं की जानकारी लेकर समय पर

समाधान किया जाए उन्होंने स्वास्थ्य योजनाओं, चिकित्सकों की उपलब्धता और एंबुलेंस सेवाओं की अद्यतन जानकारी जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में एंबुलेंस सेवाओं के सुचारु संचालन पर विशेष जोर दिया गया, ताकि जरूरतमंद मरीजों को समय पर चिकित्सा सुविधा मिल सके। बैठक की शुरुआत पूर्व साधारण सभा के पालन प्रतिवेदन की समीक्षा से हुई। इसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सहकारिता, जल जीवन मिशन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, कृषि, शिक्षा और विद्युत विभाग से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान जिले में निर्माणाधीन उप-स्वास्थ्य केंद्रों की गुणवत्ता का मुद्दा भी सामने आया। बैठक में प्रस्ताव रखा गया कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अन्य संबंधित विभागों के उपयंत्रियों से इन निर्माणाधीन केंद्रों का भौतिक सत्यापन कराया जाए। अधिकारियों को निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी करने और निर्धारित मापदंडों के अनुसार कार्य पूर्ण करने पर जोर दिया गया, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में तैयार होने वाले स्वास्थ्य केंद्रों का लाभ लोगों को बेहतर तरीके से मिल सके।

लापरवाही : खुले तार से गाय की मौत,बारिश में बिना सुरक्षा बिजली खंभे पर चढ़ा कर्मचारी

मध्य स्वर्णिम, उज्जैन।

उज्जैन में रविवार को दो अलग-अलग घटनाओं ने सरकारी कार्यों में बरती जा रही लापरवाही को उजागर किया। एक ओर सीवरेज कार्य के बाद खुले छोड़े गए बिजली के तार से करंट फैलने से एक गाय की मौत हो गई, वहीं बारिश के बीच बिना सुरक्षा उपकरण के बिजली के खंभे पर काम करते कर्मचारी का वीडियो सामने आया। पहला मामला आगर रोड स्थित नक्शत्र गार्डन के पास का है। यहां सीवरेज लाइन का काम पूरा होने के बाद ठेकेदार के कर्मचारियों ने डीपी से लिया गया बिजली कनेक्शन नहीं हटाया था। आरोप है कि खुले तार से पूरे निर्माण स्थल और आसपास की गली सड़क पर करंट फैल गया। रविवार सुबह करीब 7 बजे एक गाय करंट की चपेट में आ गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद



बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और चिमनगंज मंडी थाना पुलिस व नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा को इसकी सूचना दी। लोगों ने चिंता व्यक्त की कि यह कॉलोनी का मुख्य मार्ग है और यदि रविवार के बज्जय स्कूल खुला होता तो बड़ी जनहानि हो सकती थी। स्थानीय लोगों ने काम खत्म होने के बाद बिजली कनेक्शन न हटाने, मौके पर बैरिकेडिंग या चेतावनी बोर्ड न लगाने और डीपी से बिजली लेने की अनुमति को लेकर सवाल उठाए। वहीं, दूसरी घटना केडी गेट स्थित खजूर वाली मस्जिद के पास सामने आई। यहां बारिश के दौरान बिजली के खंभे लगाने का कार्य चल रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, एक कर्मचारी बिना हेलमेट, बिना सेफ्टी बेल्ट और किसी अन्य सुरक्षा उपकरण के ऊंचे बिजली के खंभे पर चढ़कर काम करता दिखाई दिया।

महाकाल मंदिर के सुरक्षाकर्मियों को चाकू मारने वाले का जुलूस

उज्जैन। महाकाल थाना पुलिस ने शनिवार को दो आरोपियों को जुलूस निकाला। दोनों आरोपी हाथ जोड़कर आम लोगों से माफी मांगते नजर आए। पहला आरोपी शुक्रवार को महाकालेश्वर मंदिर के बाहर पिनाकी द्वार के पास सुरक्षा व्यवस्था संचाल रहे मंदिर की क्लिक रिसर्प्स टीम (QRT) के कर्मचारी आकाश चौहान पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाला था। वहीं, दूसरा आरोपी यातायात पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करने का आरोपी है। महाकाल थाना पुलिस ने दोनों मामलों में तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। मंदिर कर्मचारी पर चाकू से हमला करने के आरोपी अंकुश परमार का पुलिस ने शक्तिपथ पर जुलूस निकाला। दूसरा आरोपी, आनंद चौहान भी महाकाल थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उस पर यातायात पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करने का आरोप है। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद महाकाल थाना पुलिस ने उसके खिलाफ भी कार्रवाई की।



जमीन विवाद में महिलाओं से मारपीट का वीडियो : खेत में काम कर रहे परिवार पर 20-25 लोगों के पहुंचने का आरोप

मध्य स्वर्णिम, उज्जैन।

जिले के खाचरौद तहसील क्षेत्र के भाटखेड़ी गांव में जमीन विवाद को लेकर विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। खेत में काम कर रही महिलाओं के साथ कथित मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद मामला पुलिस तक पहुंच गया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि कुछ लोग ट्रैक्टर और लाठी-डंडों के साथ खेत पर पहुंचे और खड़ी सोयाबीन की फसल को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से ट्रैक्टर चलाना शुरू कर दिया। महिलाओं ने जब इसका विरोध किया तो उनके साथ कथित रूप से मारपीट की गई। घटना के बाद पीड़ित परिवार और ग्रामीणों ने उज्जैन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने, आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी करने और परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है। पीड़ित पक्ष के अनुसार घटना 25 जुलाई की दोपहर की है। परिवार के सदस्य अपने खेत



में सोयाबीन की फसल की निंदाई का काम कर रहे थे। इसी दौरान करीब 20 से 25 लोग ट्रैक्टर और लाठी-डंडों के साथ खेत में पहुंचे। पीड़ितों का आरोप है कि इन लोगों ने खेत में खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलाना शुरू कर दिया। परिवार के सदस्यों ने जब इसका विरोध किया तो दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया। आरोप है कि इस दौरान महिलाओं के साथ मारपीट की गई। पीड़ित पक्ष का कहना है कि जमीन को

लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है और इसी विवाद के चलते उनके खेत में पहुंचकर दबाव बनाने का प्रयास किया गया। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि हमलावरों ने उन्हें खेत खाली करने के लिए दबाव बनाया। विरोध करने पर कथित तौर पर गाली-गलौज और मारपीट की गई। पीड़ितों का यह भी आरोप है कि उन्हें जान से मारने और जिंदा जलाने तक की धमकियां दी गईं।

गुरु पूर्णिमा से विजयादशमी तक चलेगा ‘हिंदू ही आगे’ अभियान घर-घर संपर्क के साथ जरूरतमंदों के लिए जुटाया जाएगा अनाज

मध्य स्वर्णिम, उज्जैन।

अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल ने मालवा प्रांत में संगठन के विस्तार और सामाजिक गतिविधियों को गति देने के लिए आगामी छह महीनों की विस्तृत कार्ययोजना तैयार की है। उज्जैन के मक्सी रोड स्थित प्रसंग मैरिज गार्डन में आयोजित दो दिवसीय मालवा प्रांत बैठक में संगठन विस्तार, सामाजिक सेवा और आगामी कार्यक्रमों को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में संगठन की ओर से ‘हिंदू ही आगे’ नाम से विशेष संपर्क अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया। यह अभियान गुरु पूर्णिमा से विजयादशमी तक चलाया जाएगा। अभियान के दौरान मालवा प्रांत के विभिन्न जिलों में घर-घर संपर्क कर करीब एक लाख परिवारों तक



पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। संगठन के पदाधिकारियों के अनुसार अभियान के तहत कार्यकर्ता विभिन्न क्षेत्रों में घर-घर जाकर लोगों से संपर्क स्थापित करेंगे। अभियान का उद्देश्य लोगों को धार्मिक और सामाजिक विषयों के प्रति जागरूक करना

तथा संगठन की गतिविधियों से जोड़ना बताया गया है। इसके साथ ही अभियान के दौरान घर-घर से एक मुट्ठी अनाज एकत्र करने की योजना भी बनाई गई है। एकत्रित अनाज को जरूरतमंद और वंचित परिवारों तक पहुंचाया जाएगा। संगठन ने इसे सामाजिक सहयोग और सेवा की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया है।

घर-घर संपर्क कर लोगों से संवाद करेगा संगठन

■ बैठक में संगठन की जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए प्रत्येक गांव और वार्ड में हनुमान चालीसा केंद्र शुरू करने की योजना पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा नए सदस्यों को जोड़ने और स्थानीय स्तर पर समितियों का गठन कर संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने का निर्णय लिया गया। पदाधिकारियों ने कहा कि संगठन के विस्तार के साथ सामाजिक गतिविधियों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। इसके तहत अलग-अलग स्थानों पर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनमें लोगों के ब्लड प्रेशर और शुगर की जांच की जाएगी। बैठक में आगामी छह महीनों के लिए विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और संरचनात्मक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तय की गई। इसमें गुरु पूर्णिमा उत्सव, 14 अगस्त को अखंड भारत संकल्प दिवस, शरत् पूजन और गणेश उत्सव के दौरान ‘माय फैंड गणेश’ अभियान सहित विभिन्न कार्यक्रम शामिल हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर साधु-संतों के सम्मान का कार्यक्रम आयोजित करने की योजना भी बनाई गई है। पदाधिकारियों ने आगामी कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपने और विभिन्न स्तरों पर समन्वय के साथ काम करने पर जोर दिया।

25,800 रुपए का सामान जब्त

मंदसौर में घर में चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, पूरा माल बरामद

मध्य स्वर्णिम, मंदसौर।

शहर में घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले एक आरोपी को कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी किया गया पूरा सामान बरामद करने का दावा किया है। बरामद सामान की कुल कीमत करीब 25,800 रुपए बताई गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है और अब उससे शहर में हुई अन्य चोरी की घटनाओं के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस के अनुसार चोरी की यह वारदात 500 क्वार्टर टिगरिया अभिनंदन नगर क्षेत्र में हुई थी। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की और घटनास्थल तथा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। इसके साथ ही मुखबिर तंत्र और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से आरोपी की पहचान की गई। टिगरिया अभिनंदन नगर निवासी हर्ष धानक (21) ने



कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अज्ञात बदमाश उसके घर में घुसकर कीमती सामान चोरी कर ले गया है। चोरी गए सामान में एप्पल कंपनी के एयरबड्स, पावर बैंक, चांदी की अंगूठी, चांदी का सिक्का और 800 रुपए नकद शामिल थे। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ आसपास के

सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की बाली की से जांच की। जांच के दौरान पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से महत्वपूर्ण सुराग मिले। इसके बाद पुलिस ने मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर सदिग्ध की पहचान करने का प्रयास किया। जांच में मिले सुरागों के आधार पर पुलिस ने 500 क्वार्टर टिगरिया अभिनंदन नगर निवासी 27 वर्षीय जुबेर हुसैन पिता मोहम्मद हुसैन को हिरासत में लेकर पूछताछ की।



नीट पेपर लीक : छात्रों की मौत पर कैंडल मार्च : सिवनी मालवा में कांग्रेस-एनएसयूआई ने न्याय की मांग

मध्य स्वर्णिम, सिवनी मालवा।
सिवनी मालवा में शनिवार रात कांग्रेस और NSUI कार्यकर्ताओं ने N.E.T पेपर मामले को लेकर कैंडल मार्च निकाला। कल्लू चौक से गांधी चौक तक निकाले गए मार्च में आयोगजनों के अनुसार, मामले में जान गंवाने वाले 22 छात्रों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से छात्रों को न्याय दिलाने और परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की। कैंडल मार्च में कांग्रेस और हस्तु के कार्यकर्ता हाथों में मोमबत्तियां लेकर शामिल हुए। गांधी चौक पहुंचने

के बाद कार्यकर्ताओं ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत छात्रों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग उठाई गई। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष प्रवीण रघुवंशी ने कहा कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि युवाओं का शिक्षा व्यवस्था पर विश्वास बना रहना जरूरी है। यदि किसी स्तर पर लापरवाही हुई है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। रघुवंशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी छात्रों को न्याय दिलाने की मांग की।

दौड़ का शोर गूंजा....



नर्मदापुरम। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध हिल स्टेशन पचमढ़ी में रविवार को 8वीं पचमढ़ी मानसून मैराथन-2026 का आयोजन हुआ। सतपुड़ा की हरियाली और हल्की बारिश के बीच देश-विदेश के 1600 से अधिक धावकों ने दौड़ लगाई। मैराथन के जरिए रन फॉर टाइगर और प्लास्टिक फ्री पचमढ़ी का संदेश दिया गया। मैराथन को नर्मदापुरम सांसद दर्शन सिंह चौधरी और मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के ज्वाइंट डायरेक्टर डॉ. संतोष कुमार श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आयोजन में भारत के अलावा अमेरिका, स्वीडन, मंगोलिया और पेरु से आए अंतरराष्ट्रीय धावकों ने भी हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग, जिला प्रशासन और एक्वेचंस एंड यू के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित मैराथन में 5, 10, 21 और 42 किलोमीटर की दौड़ हुई। इसमें 4 वर्ष के नन्हें प्रतिभागी से लेकर 84 वर्ष के वरिष्ठ धावकों तक ने उत्साह के साथ भाग लिया। सबसे चुनौतीपूर्ण 42 किलोमीटर की फुल मैराथन पर्वतीय मार्ग पर आयोजित की गई। मैराथन की शुरुआत 42 किलोमीटर दौड़ के साथ सुबह 6 बजे हुई। इसके बाद सुबह 6-45 बजे 21 किलोमीटर, सुबह 7-45 बजे 10 किलोमीटर और सुबह 8 बजे 5 किलोमीटर फन रन शुरू हुई। मैराथन में मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की क्षेत्र संचालक राखी नंदा ने 5 किलोमीटर दौड़ में भाग लेकर प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया।

मुलाकात का समय दो बार बदला, सुबह 4 बजे से तैयारी में जुटे रहे किसान

भोपाल बुलाकर सीएम के दिल्ली जाने से किसान नाराज : बीच रास्ते से लौटे किसान नेता

मध्य स्वर्णिम, नर्मदापुरम।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात के लिए रविवार को भोपाल रवाना हुए संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों को बीच रास्ते से ही वापस लौटना पड़ा। किसान नेताओं के अनुसार, मुख्यमंत्री से मुलाकात का कार्यक्रम पहले तय किया गया था, लेकिन रविवार दोपहर अचानक मुख्यमंत्री के दिल्ली रवाना होने की सूचना मिलने के बाद प्रस्तावित बैठक नहीं हो सकी। इससे नाराज किसान संगठनों ने नर्मदापुरम लौटकर कृषि उपज मंडी में आपात बैठक की और आंदोलन को और तेज करने का फैसला लिया। किसान नेताओं ने सरकार के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि किसानों को मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए बुलाया गया था तो उन्हें बिना मिले वापस लौटना उचित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसान संगठनों के प्रतिनिधि सुबह से मुख्यमंत्री से मिलने की तैयारी कर रहे थे और कई किसान नेता अलग-अलग क्षेत्रों से भोपाल के लिए रवाना भी हो चुके थे। इसी दौरान मुख्यमंत्री के दिल्ली रवाना होने की सूचना मिली। संयुक्त किसान मोर्चा ने अब 27 जुलाई को नर्मदापुरम के सेठानी घाट से भोपाल के लिए पैदल मार्च निकालने का निर्णय लिया है।



सेठानी घाट से सोमवार सुबह शुरू होगा पैदल मार्च

■ किसान नेताओं के मुताबिक, 29 जुलाई की शाम तक भोपाल पहुंचने का प्रयास किया जाएगा और 30 जुलाई से मुख्यमंत्री निवास के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। किसानों ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी मांगों पर सरकार ठोस निर्णय नहीं लेती, आंदोलन जारी रहेगा। क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष लीलाधर राजपूत ने बताया कि शनिवार को जिला प्रशासन के साथ हुई बैठक के बाद 26 जुलाई को मुख्यमंत्री से किसानों की मुलाकात कराने का कार्यक्रम तय हुआ था। इसके बाद रात में नर्मदापुरम एडीएम की ओर से संदेश मिला कि रविवार सुबह 9 बजे मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी। उन्होंने बताया कि किसान प्रतिनिधि सुबह करीब 4 बजे से ही उठकर मुलाकात की तैयारी में जुट गए थे। इसके बाद सुबह करीब 6 बजे संदेश आया कि मुलाकात का समय बदल गया है और नया



किसान बोले- सम्मान के साथ खिलवाड़, अब आंदोलन होगा तेज

■ इसके बाद करीब 10 बजे किसानों को शाम 6 बजे मुख्यमंत्री से मिलने की जानकारी दी गई। मुलाकात की उम्मीद में किसान नेता और पदाधिकारी अलग-अलग गांवों और शहरों से भोपाल के लिए रवाना हो गए। कुछ किसान नेता नर्मदा पुल के पास पहुंच चुके थे, जबकि कुछ बुधनी और रोहना क्षेत्र में थे। इसी दौरान दोपहर करीब 3 बजे अपर कलेक्टर की ओर से फोन कर जानकारी दी गई कि मुख्यमंत्री दिल्ली रवाना हो गए हैं और अगले दो दिन भोपाल में उनकी मुलाकात संभव नहीं होगी। यह सूचना मिलते ही किसान नेताओं ने वापस नर्मदापुरम लौटने का फैसला किया। सभी पदाधिकारी कृषि उपज मंडी पहुंचे, जहां तत्काल आपात बैठक आयोजित कर आगे की रणनीति तैयार की गई। किसान संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा कि किसानों को मुख्यमंत्री से मिलने के लिए बुलाया गया था। इसके बाद मुलाकात का समय लगातार बदला गया और अंत में मुख्यमंत्री के दिल्ली चले जाने की जानकारी दी गई। किसान नेताओं ने इसे किसानों के सम्मान के साथ खिलवाड़ बताया। किसान नेताओं का कहना है कि किसान अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से प्रशासन और सरकार के सामने अपनी बात रख रहे हैं। यदि सरकार उनकी समस्याओं पर चर्चा करना चाहती है तो किसानों को उचित समय देकर उनकी बात सुनी जानी चाहिए।

इटारसी में देवरानी ने जेठानी का कान दांतों से काटा, 90% हिस्सा क्षतिग्रस्त



मध्य स्वर्णिम, इटारसी।

नर्मदापुरम जिले के केसला ब्लॉक के पिपरिया कला गांव में खेत की बटाई और 1,000 के लेनदेन को लेकर पारिवारिक विवाद इतना बढ़ गया कि एक महिला ने कथित तौर पर अपनी जेठानी के कान पर दांतों से हमला कर दिया। हमले में महिला के कान का करीब 90 प्रतिशत हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। घायल महिला को इलाज के लिए शासकीय अस्पताल इटारसी में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका उपचार जारी है। पीड़िता की पहचान रवीना कासदे (27) के रूप में हुई है। घटना करीब छह दिन पहले सोमवार सुबह लगभग 10 बजे की बताई जा रही है। शनिवार को डॉक्टरों ने बताया कि महिला के

कान के पुनर्निर्माण के लिए ऑपरेशन किया जाएगा पीड़िता के अनुसार, परिवार में करीब एक एकड़ खेत की बटाई को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। रवीना का कहना है कि उसने खेत को तैयार कराने के लिए करीब 1,000 खर्च किए थे। खेत को लेकर विवाद होने के बाद उसने अपनी खर्च की गई राशि वापस मांगी थी। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहसुनी शुरू हो गई महिला का आरोप है कि विवाद के दौरान दूसरी महिला ने खेत जोतने से इनकार कर दिया और उसके खर्च किए गए रुपए वापस करने से भी मना कर दिया। मामला बढ़ने पर पीड़िता ने गांव के सरपंच को बुलाने की बात कही, लेकिन सरपंच मौके पर नहीं पहुंच सके।

आरके चौधरी को मिली बुधनी की जिम्मेदारी

वन विभाग का डैमेज कंट्रोल... यारनगर में इको सेंसिटिव जोन पाबंदी की तैयारी

मध्य स्वर्णिम, नर्मदापुरम/सीहोर।
बुधनी के यारनगर इलाके में वन भूमि और राजस्व भूमि के सीमांकन को लेकर शुरू हुआ विवाद अब प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर तूल पकड़ता नजर आ रहा है। क्षेत्र में कथित अवैध रिसॉर्ट निर्माण और वन भूमि पर गतिविधियों को लेकर सवाल उठने के बाद वन विभाग ने अब सख्ती के संकेत दिए हैं। इसी बीच विभाग में प्रशासनिक फेरबदल करते हुए बुधनी की उप वन मंडलाधिकारी (एसडीओ) सुकृति ओसवाल को हटा दिया गया है। उनकी जगह आरके चौधरी को बुधनी का नया एसडीओ बनाया गया है। यारनगर में वन भूमि और राजस्व भूमि की सीमाओं को स्पष्ट करने की मांग को लेकर क्षेत्रीय विधायक रमाकांत भार्गव ने कलेक्टर, सीहोर को पत्र लिखा था।



इस पत्र के बाद एसडीओ सुकृति ओसवाल ने मामले में सक्रियता दिखाते हुए पत्र को वन मंडलाधिकारी, सीहोर को अग्रसारित किया था। साथ ही सीमांकन की प्रक्रिया को लेकर उचित मार्गदर्शन भी मांगा गया था। अब इस पूरे मामले के बीच हुए प्रशासनिक फेरबदल को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। यारनगर क्षेत्र में लंबे समय से रिसॉर्ट और अन्य निर्माण गतिविधियों को लेकर सवाल उठते रहे हैं। आरोप है कि वन क्षेत्र से सटे इलाकों में नियमों की अनदेखी कर निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। स्थानीय स्तर पर कुछ रसूखदार रिसॉर्ट संचालकों को कथित संरक्षण और अधिकारियों की मिलीभगत के आरोप भी लगाए गए हैं। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

कारगिल विजय दिवस पर पूर्व सैनिक सम्मानित



पिपरिया। पिपरिया के सुभाष चौक पर कारगिल विजय दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व सैनिक संगठन पिपरिया, बनखेड़ी और पचमढ़ी की ओर से कारगिल युद्ध में हिस्सा लेने वाले पूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया। रविवार को आयोजित इस कार्यक्रम में भारत माता के जयघोष के साथ देश के अमर शहीदों को याद किया गया। विधायक ठाकुर दास नागवंशी और नगरपालिका अध्यक्ष नीना नवनीत नागपाल ने शहीदों को पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। पूर्व सैनिक संगठन के पदाधिकारियों ने कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना के शौर्य और ऐतिहासिक जीत पर अपने विचार रखे। इस मौके पर उपस्थित अतिथियों और नागरिकों ने कारगिल युद्ध में शामिल रहे क्षेत्र के पूर्व सैनिकों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया।

ट्रक एसोसिएशन ने सिलारी टोल पर लगाया जाम, डेढ़ घंटे तक थमे वाहनों के पहिए

मध्य स्वर्णिम, पिपरिया।

पिपरिया-जबलपुर स्टेट हाईवे पर सिलारी टोल प्लाजा के खिलाफ रविवार को पिपरिया ट्रक एसोसिएशन ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सड़क की जर्जर हालत, जगह-जगह बने गड्ढे और पर्याप्त सुविधाओं के अभाव के बावजूद टोल वसूली किए जाने का आरोप लगाते हुए ट्रक संचालकों ने टोल प्लाजा के पास चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शन के चलते पिपरिया-बनखेड़ी मार्ग पर करीब डेढ़ घंटे तक यातायात पूरी तरह बाधित रहा और सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जिस सड़क के रखरखाव और बेहतर यातायात सुविधा के नाम पर वाहन चालकों से टोल वसूला जा रहा है, उसी सड़क की हालत लगातार खराब होती जा रही है। हाईवे पर जगह-जगह गड्ढे गड्ढे होने के कारण वाहन



चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद टोल वसूली शुरू किए जाने से ट्रक ऑपरेटर्स और स्थानीय लोगों में नाराजगी है। ट्रक एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि टोल वसूली से जुड़ी कथित अनियमितताओं और सड़क की खराब स्थिति को लेकर पहले ही मंगलवार थाने

में ज्ञापन सौंपकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई गई थीं। इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने पर रविवार को एसोसिएशन ने आंदोलन का रास्ता अपनाया। प्रदर्शन के दौरान ट्रकों को पिपरिया-बनखेड़ी मार्ग पर आड़ा-तिरछा खड़ा कर दिया गया। देखते ही देखते मार्ग पर वाहनों की आवाजाही रुक गई। जाम की सूचना मिलते ही मंगलवारा थाना प्रभारी आदित्य सेन पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।



मध्य स्वर्णिम, नर्मदापुरम।

नर्मदापुरम संभाग के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र मोहासा में ग्रीन एनर्जी सेक्टर तेजी से आकार ले रहा है। क्षेत्र में सौर ऊर्जा और रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े छह बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इनमें रू सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का सोलर सेल यूनिट प्लांट तैयार हो चुका है और अब यहां उत्पादन शुरू करने की तैयारियां की जा रही हैं। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अगस्त के पहले सप्ताह में मोहासा पहुंचकर प्लांट का उद्घाटन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री के संभावित दौरों को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री के दौरे और उद्घाटन कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर



शुक्रवार को कलेक्टर सोमेश मिश्रा, एसपी साई कृष्णा एस. थोटा और जिला पंचायत सीईओ हिमाशु जैन ने एसडीएम तथा एमपीआईडीसी के अधिकारियों के साथ मोहासा औद्योगिक क्षेत्र का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने रू सोलर एनर्जी प्लांट के साथ कार्यक्रम स्थल और प्रस्तावित

ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में बड़े निवेश की तैयारी

■ वहीं इंडस्ट्री कॉन्वलेव के दौरान मोहासा क्षेत्र के लिए करीब 18 हजार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। औद्योगिक क्षेत्र के फेस-2 के लिए भी कई निवेशक जमीन का निरीक्षण कर रहे हैं। एमपीआईडीसी के एनर्जीयूटिल डायरेक्टर संदीप अस्थाना के अनुसार मोहासा में सोलर एनर्जी से संबंधित कंपनियों के प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। रू सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की सेल यूनिट बनकर तैयार हो चुकी है। कंपनी ने यहां 200 से अधिक कर्मचारियों की भर्ती भी की है। हालांकि प्लांट की दूसरी यूनिट का काम अभी शुरू होना बाकी है। अधिकारियों के मुताबिक परियोजनाओं के पूरी तरह संचालन में आने के बाद क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे।

नीट पेपर लीक के विरोध में छात्रों ने निकाला मशाल जुलूस, दिवंगत छात्रों को दी श्रद्धांजलि

मध्य स्वर्णिम, पिपरिया।

कथित हथशस्त्र पेपर लीक प्रकरण और परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग को लेकर शनिवार को पिपरिया में छात्रों, अभिभावकों और जागरूक नागरिकों ने शांतिपूर्ण मशाल जुलूस निकाला। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन (SOP) के नेतृत्व में आयोजित इस जुलूस में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं, उनके अभिभावक और क्षेत्र के नागरिक शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रतियोगी परीक्षाओं को निष्पक्ष बनाने की मांग उठाई। मशाल जुलूस की शुरुआत काली मंदिर से हुई। छात्र हाथों में मशाल लेकर पैदल सुभाष चौक पहुंचे। इस दौरान प्रतिभागियों ने शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद की। छात्रों ने कहा कि



और भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाने की मांग की। जुलूस के दौरान छात्रों ने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्रों की एकजुटता को भी आंदोलन का हिस्सा बताया।

